Knowledgeable Research (An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal) **ISSN 2583-6633**
Available Online: http://knowledgeableresearch.com Vol.03, No.3, October 2024
Page-:62-66

पंचायती राज व्यवस्था और डिजिटल शासन से संबंधित नीतियां एवं पहलें

मृदुल पटेल (शोध छात्र), समाजशास्त्र विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, (म. प्र.)
डॉ. सुशीला माहौर, प्राचार्य, शासकीय वी. आर. जी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरार ,ग्वालियर, (म. प्र.)

****

शोध सार - *यह शोध पत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने में डिजिटल शासन से संबंधित नीतियों और पहलों के संबंध एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। सरकारी रिपोर्टों, अकादमिक प्रकाशनों और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों सहित विभिन्न स्रोतों से द्वितीयक आंकड़ों का लाभ उठाते हुए अध्ययन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सामुदायिक सशक्तिकरण में डिजिटल शासन से संबंधित नीतियों और पहलों की भूमिका को उजागर करना है। पेपर पंचायती राज व्यवस्था के भीतर व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने, डिजिटल प्लेटफार्मों की पहुंच, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कौशल विकास और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लोकतंत्रीकरण का विश्लेषण करने में डिजिटल शासन से संबंधित नीतियों और पहलों की भूमिका की पड़ताल करता है। यह अध्ययन निष्कर्ष के रूप में डिजिटलीकरण द्वारा स्थानीय स्तर पर लाए गए परिवर्तनों के बारे एक व्यापक दृष्टि प्रदान करता है।*

मुख्य शब्द - *पंचायती राज व्यवस्था, डिजिटल शासन, डिजिटलीकरण, प्रौद्योगिकी, सामुदायिक सशक्तिकरण, लोकतंत्रीकरण।*

****

प्रस्तावना –

समकालीन समाज में भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में डिजिटलीकरण और सामुदायिक सशक्तिकरण के मध्य आपसी संबंध विद्वानों की जांच का केंद्र बिंदु बन गया है। यह शोध पंचायती राज की विकेंद्रीकृत शासन संरचना के अंतर्गत समुदायों की गतिशीलता पर डिजिटल प्रगति के निहितार्थ को उजागर करने के लिए एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण पर आधारित है। विश्व आज विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी एकीकरण में अभूतपूर्व वृद्धि देख रही है, अतः इस डिजिटल प्रगति के समाजशास्त्रीय आयामों की जांच करना अनिवार्य हो जाता है। पंचायती राज प्रणाली, स्थानीय शासन और सामुदायिक भागीदारी पर जोर देने के साथ, यह समझने के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करती है कि कैसे डिजीटल शासन से संबंधित नीतियां एवं पहलें स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में बढ़ी हुई पहुंच , भागीदारी और समावेशिता को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं। इस शोध के माध्यम से मेरा उद्देश्य इस बात की पड़ताल करना है कि डिजीटल शासन से संबंधित सरकार कौन-कौन सी नीतियां एवं पहलें स्थानीय स्तर पर समुदायों को पंचायती राज की विकेंद्रीकृत शासन संरचना के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पहुंच, भागीदारी और समावेशिता को बढ़ावा दे रही हैं।

अध्ययन का उद्देश्य -

1. पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर चलाई जा रही डिजिटल शासन से संबंधित नीतियों और पहलों के बारे में जानना।
2. स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में बढ़ी हुई पहुंच, भागीदारी और समावेशिता को बढ़ावा देने में डिजिटल शासन से संबंधित नीतियों और पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

Knowledgeable Research (An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal) **ISSN 2583-6633**
Available Online: http://knowledgeableresearch.com Vol.03, No.3, October 2024
Page-:62-66

अध्ययन की आवश्यकता -

डिजिटलीकरण के आगमन ने अभूतपूर्व कनेक्टिविटी और सूचना पहुंच के युग की शुरुआत की है। हालाँकि, पंचायती राज की विकेंद्रीकृत शासन संरचनाओं पर इसका सूक्ष्म प्रभाव शोध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। अतः वर्तमान में यह अध्ययन करने की अनिवार्य आवश्यकता है कि डिजिटल शासन से संबंधित नीतियां और पहलें किस प्रकार स्थानीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में बढ़ी हुई पहुंच , भागीदारी और समावेशिता को बढ़ावा देता है ।

भारत में पंचायती राज प्रणाली और डिजिटल शासन से संबंधित सरकारी नीतियां और पहलें -

1. डिजिटल इंडिया -

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है। इसमें डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने, डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रम और नीतियां शामिल हैं। ये पहल पंचायती राज क्षेत्रों के निवासियों के लिए डिजिटल उपकरणों को अधिक सुलभ बनाने में योगदान करती हैं।

2. ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) -

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत ई-पंचायत एमएमपी देश भर में पंचायती राज संस्थानों के कामकाज को स्वचालित और नेटवर्किंग करने पर केंद्रित है। इसमें प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता में सुधार करने और स्थानीय निर्णय लेने में नागरिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए विभिन्न ई-गवर्नेंस टूल और एप्लिकेशन का कार्यान्वयन शामिल है।

3. PRIAsoft (पंचायती राज संस्थान लेखांकन सॉफ्टवेयर) -

PRIAsoft भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसे वित्तीय रिकॉर्ड, बजट और लेखांकन बनाए रखने में पंचायती राज संस्थानों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। डिजिटल उपकरण स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन में वित्तीय पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

4. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) -

एनआरएलएम एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विविध और लाभकारी स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर गरीबी को कम करना है। मिशन कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और बाजार पहुंच, आर्थिक उत्थान में योगदान और जमीनी स्तर पर निर्णय लेने में भागीदारी सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए डिजिटल टूल का लाभ उठाता है।

5. स्वामित्व योजना -

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। इसमें संपत्ति कार्ड बनाने के लिए ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाली भूमि के सर्वेक्षण सहित प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। यह पहल संपत्ति रिकॉर्ड को बेहतर बनाने और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने में योगदान देती है।

6. MyGov प्लेटफॉर्म -

MyGov एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को शासन और नीति-निर्माण में संलग्न करता है। यह नागरिकों को चर्चाओं में भाग

Knowledgeable Research (An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal) **ISSN 2583-6633**
Available Online: http://knowledgeableresearch.com Vol.03, No.3, October 2024
Page-:62-66

लेने, विचार साझा करने और विभिन्न सरकारी पहलों पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक स्थान प्रदान करता है। यह एक नागरिक सहभागिता मंच है जिसे सहभागी शासन को सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित किया गया है। वर्तमान में, डलळवअ के साथ 2.76 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता पंजीकृत हैं, जो डलळवअ प्लेटफॉर्म पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। इस मंच में ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित चर्चाएं, निर्णय लेने में समावेशिता को बढ़ावा देना शामिल है।

7. भारतनेट परियोजना -

भारतनेट परियोजना का लक्ष्य देश की सभी ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर, यह पहल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई-गवर्नेंस सेवाओं और सूचना तक पहुंच बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में समुदायों को सशक्त बनाने में योगदान देती है।डिजिटल गांवः डमपजल् ने अक्टूबर, 2018 में 'डिजिटल गांव पायलट परियोजना' भी शुरू की है। इस परियोजना के तहत प्रति राज्यध्केंद्र शासित प्रदेश प्रति जिले में कम से कम एक ग्राम पंचायतध्गांव के साथ 700 ग्राम पंचायत (जीपी)ध्गांव को कवर किया जा रहा है। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवा, वित्तीय सेवाएं, कौशल विकास, सरकार से नागरिक सेवाएं (जी2सी), व्यवसाय से नागरिक (बी2सी) सेवाएं सहित सौर पैनल संचालित स्ट्रीट लाइट जैसी डिजिटल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

8. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमडीएसए) -

सरकार ने ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता लाने के लिए 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को शामिल करके "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)" नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। इसमें 6.63 करोड़ पंजीकृत उम्मीदवार हैं और इनमें से 5.69 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 4.22 करोड़ को प्रमाणित किया गया है।

9. कॉमन सर्विस सेंटर -

सीएससी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से डिजिटल मोड में सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं । इन सीएससी द्वारा 400 से अधिक डिजिटल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अब तक, देश भर में 5.21 लाख सीएससी (शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित) कार्यात्मक हैं, जिनमें से 4.14 लाख सीएससी ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यात्मक हैं। राजस्थान राज्य में 23,035 सीएससी कार्यात्मक हैं, जिनमें से 18823 सीएससी ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यात्मक हैं।

डिजिटल शासन से संबंधित नीतियों और पहलों का स्थानीय शासन पर प्रभाव -

1- पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में, डिजिटल उपकरण, ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकी-संचालित पहल ने स्थानीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में बढ़ी हुई पहुंच, भागीदारी और समावेशिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

2- डिजिटल शासन से संबंधित नीतियों और पहलों ने भौगोलिक बाधाओं को कम करके उन्नत पहुंच में बढ़ावा दिया है, जिससे दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के लोगों को स्थानीय शासन प्रक्रियाओं तक पहुंचने और जुड़ने में मदद मिल रही है । ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तैनाती के माध्यम से, व्यक्ति भौतिक दूरी की बाधाओं के बिना चर्चाओं में भाग ले सकते हैं,

Knowledgeable Research (An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal) **ISSN 2583-6633**
Available Online: http://knowledgeableresearch.com Vol.03, No.3, October 2024
Page-:62-66

प्रासंगिक जानकारी तक पहुंच सकते हैं और निर्णय लेने में योगदान कर सकते हैं।

3- ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म सूचना केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। ये समुदाय के सदस्यों तक नीतियों, पहलों और निर्णयों के बारे में महत्वपूर्ण विवरण प्रसारित करते हैं। यह पारदर्शिता व्यक्तियों को ज्ञान के साथ सशक्त बनाती है, जिससे वे स्थानीय निर्णय लेने में सूचित योगदान देने में सक्षम होते हैं।

4- आज बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म समुदाय के सदस्यों को व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता के बिना चर्चाओं में भाग लेने, चिंताओं को व्यक्त करने और विचारों में योगदान करने में सक्षम बनाते हैं। इससे स्थानीय स्वशासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में समावेशिता को बढ़ावा मिलता है।

5- डिजिटल उपकरण सर्वेक्षण करने और समुदाय के सदस्यों से प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। ऑनलाइन सर्वेक्षणों और फीडबैक फॉर्मों के माध्यम से, स्थानीय अधिकारी विभिन्न मुद्दों पर जनता की राय जान सकते हैं, जिससे भागीदारीपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। यह समावेशिता विविध दृष्टिकोणों को शामिल करने की अनुमति देती है, जिससे पंचायती राज प्रणाली के भीतर लिए गए निर्णयों की गुणवत्ता समृद्ध होती है।

6- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फोरम समावेशी निर्णय लेने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। आभासी चर्चा बोर्ड और सहयोगी मंच समुदाय के सदस्यों को अपनी राय व्यक्त करने, विचारों का प्रस्ताव करने और विचार-विमर्श प्रक्रियाओं में संलग्न होने की अनुमति देते हैं। डिजिटल उपकरण यह सुनिश्चित करते हैं कि हाशिये पर पड़े लोगों की आवाजें न केवल सुनी जाएं बल्कि निर्णय लेने के ढांचे में सक्रिय रूप से विचार भी किया जाए, जिससे अधिक समावेशी शासन संरचना को बढ़ावा मिले।

निष्कर्ष -

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पंचायती राज प्रणाली के भीतर डिजिटल शासन से संबंधित नीतियों और पहलों ने बाधाओं को तोड़ने, पहुंच बढ़ाने और स्थानीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समावेशिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह डिजिटल परिवर्तन समुदायों को स्थानीय स्तर पर शासन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा लोगों को स्थानीय शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक उपकरण और मंच प्रदान करके सशक्त बना रहा है।

सन्दर्भ सूची -

1- कोचर, समीर . ई-गवर्नेंस नीड फॉर ए बॉटम-अप-अप्रोच . योजना, जनवरी 2013. पृष्ठ 23-26.

2- ‘‘गवर्नमेंट एम्स टू गिव डिजिटल इंडिया बेनिफिट्स टू फॉर्मर: पीएम मोदी . द टाइम्स ऑफ इंडिया, 18 फरवरी 2016.

3- गुलाटी, अर्चना जी. आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस. कुरुक्षेत्र, जुलाई 2017. पृष्ठ 17-19.

4- मन्नथुकरन, निसिम. द ग्रैंड डिल्यूजन ऑफ डिजिटल इंडिया . द हिंदू. 26 फरवरी 2017.

5- चौधरी, सिम्मी. ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट ऑफ डिजिटल इंडिया. योजना, दिसंबर 2018. पृष्ठ 29-32.

6- कटरागड्डा, ललितेश. डिजिटल इंडिया - एट द हार्ट ऑफ पूर्ण स्वराज. योजना, दिसंबर 2018. पृष्ठ 34-37.

7- प्रजापति रिंकूबेन जी. और गवली पी.आर. डिजिटल पंचायत - ए स्टडी. पुणे रिसर्च डिस्कवरी. खंड 4, अंक 3.

Knowledgeable Research (An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal) **ISSN 2583-6633**
Available Online: http://knowledgeableresearch.com Vol.03, No.3, October 2024
Page-:62-66

8- मिश्रा, अविनाश और दत्ता, मधुबंती. ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड . कुरूक्षेत्र, दिसंबर 2022. पृष्ठ 5-10.

9- दाधीच, बालेन्दु शर्मा. मोबाइल गवर्नेंस. कुरूक्षेत्र, दिसंबर 2022. पृष्ठ 24-28.

10- ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण. PIB Press Release 2 Aug 2023.

11- https://egyankosh.ac.in/handle/123456789/63048

12- https://www.drishtiias.com/hindi/national-organization/panchayati-raj-iinstitution-pri

13- https://m.timesofindia.com/india/states-told-to-equip-all-panchayats-to-accept-digital-payments-by-august-15/articleshow/101376039.cms

14- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1927237

15- https://government.economictimes.indiatimes.com/news/governance/egramswaraj-digitization-transforming-panchayati-raj-institutions-union-minister-kapil-moreshwar-patil/92996793

16- https://www.businessworld.in/article/Centre-Advances-e-Panchayat-Mission-Mode-Project-Under-Digital-India-Programme-/06-12-2023 50128

17- https://egov.eletsonline.com/2023/10/elets-national-rural-egovernance-summit-2023-building-a-vibrant-rural-ecosystem-in-the-digital-age/

Corresponding Author: Mridul Patel
E-mail: mridulpatel92@gmail.com
Received 1 October 2024; Accepted 15 October 2024. Available online: 30 October, 2024
Published by SAFE. (Society for Academic Facilitation and Extension)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License